(a) whether Government (Municipal Corporation of Delhi/Delhi Police) have received complaints in regard to unsafe condition in Pocket 'A', Phase-III, Ashok Vihar, Delhi-52;

(b) if so, what are the details thereof; and

(c) what action Government have taken/propose to take to safeguard the interest of the residents of that Block?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME MINISTER (SHRI P. M. SAYEED): (a) to (c) The Municipal Corporation of Delhi has reported that no complaint about unsafe condition in pocket 'A', Phase-III, Ashok Vihar, has been received. Complaints about repairs of roads, paths, etc., are attended to regularly by the Corporation.

Interstate Crimes

4030. SHRI J. S. RAJU: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) how many interstate crimes took place in the country during the last three years, year-wise figures;

(b) how many were solved among them, year-wise figures;

(c) how many are still pending for final disposal/solution among them, year-wise figures;

(d) whether there is any proposal to create a separate organisation other than CBI to tackle the interstate crimes, if so, what are the specific reasons thereof;

(e) whether any study was conducted before recommending such a step, if so, details of the study;

(f) whether it is a fact that CBI is against bifurcation of the organisation and creation of another organisation to tackle the interstate crimes; and

(g) whether Government will constitute a high level committee to study all aspects of this issue before taking a final decision, if the answer is negative, reasons for the same?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI P. M. SAYEED): (a) to (c) The National Crime Records Bureau compiles data under major crime heads. It does not separately compile data on interstate crimes.

(d) to (g) The Thirteenth Report of the Estimates Committee of the Tenth Lok Sabha had recommended setting up of a separate National Police Agency under the Ministry of Home Affairs. The Estimates Committee had further recommended that the National Police Agency should focus on crimes of national and trans-national importance, whereas the CBI should focus on anti-corruption work.

The recommendations of the Estimates Committee were examined by the Central Government and it was felt that there would be no distinct advantage in creating such a separate body as it would also be subject to the same problems and difficulties that are experienced in the present system.

दंगों में पीड़ित/मृत व्यक्तियों को राहत

4031. श्री दिलीप सिंह जूदेव: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिसम्बर, 1992 से जून, 1993 तक की अवधि के दौरान देश में दंगों और प्राकृतिक आपदाओं में पीड़ितों और मृतकों के परिवारों को किस आधार पर आर्थिक सहायता और पेंशन तथा अनुकम्पा नियुक्ति दी गई है;

(ख) क्या उक्त सहायता, पेंशन और अनुकम्पा नियुक्ति सभी प्रकार के दंगा पीड़ितों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित व्यक्तियों को समान रूप से दी जा रही है और भविष्य में भी दी जाएगी; और

(ग) इस अवधि के दौरान स्वीकृत मामलों और उपर्युक्त सहायता से लाभान्वित व्यक्तियों और परिवारों के संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद): (क) से (ग) सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखना राज्य का विषय है तथा यह उनका ही दायित्व है कि वे समय समय पर अपने द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार दंगा पीड़ितों को राहत उपाय मुहैया करवाएं। तथापि, केन्द्रीय सरकार ने सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए है कि आदर्श मानकों के अनुसार साम्प्रदायिक दंगों के शिकार व्यक्ति की मौत हो जाने की स्थिति में एक लाख रुपए की अनुग्रह राशि तथा स्थायी रूप से अक्षम हो जाने पर 50,000 रु० की राशि का भुगतान किया जाए। अयोध्या की घटना से संबंधित साम्प्रदायिक दंगों के मामले में मृतक के निकट संबंधी को दो लाख रु० की अनुग्रह-पूर्वक राहत एक बार के अपवाद के रूप में देने का सुझाव दिया गया। इसके अलावा, परिवार के कमाने वाले सदस्य के मारे जाने अथवा स्थायी रूप से अक्षम हो जाने की स्थिति में उसकी विधवा या बच्चों को रोजगार देने, बेघर हुए लोगों को मकान और मकान स्थलों का आवंटन करने, परिवारों को अपना कारोबार फिर से शुरू करने के लिए दुकानों/कियोस्कों के लिए स्थान का आवंटन तथा दंगों से प्रभावित हुए उद्योगों तथा कारोबार के लिए बैंक ऋण देने का भी